



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4 ]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2000/पौष 16, 1921

No. 4]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2000/PAUSA 16, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2000

**विषय :** यूरोपीय संघ (ईयू) तथा ताईवान से आयातित बिसफिनोल-ए के संबंध में पाटन-रोधी जांच शुरू करना।

सं. 47/1/99/डीजीएडी.—मैसर्स केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमि., 7, नागिन महल, 82 बी. एन. रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400020 ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें यूरोपीय संघ तथा ताईवान से बिसफिनोल-ए के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

1. **शामिल उत्पाद:** वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद यूरोपीय संघ तथा ताईवान मूल के अथवा वहां से निर्यातित बिसफिनोल-ए है (जिसे इसके पश्चात् सम्बद्ध वस्तु भी कहा गया है) बिसफिनोल-ए का उपयोग फिनोलिक रेजिन, ईपोक्सी रेसिन, पोलिकारबोनेट रेजिन तथा अनसैवचुरेटिड पोलियस्टर रेजिन में किया जाता है और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा-शुल्क उप-शीर्ष 2907.23 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के मामले में बाध्यकर नहीं है।
2. **घरेलू उद्योग की हैसियत:-** मैसर्स केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड, मुम्बई भारत में बिसफिनोल-ए का एकमात्र उत्पादक है और इसलिए याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की मूलभूत शर्तों को पूरा करता है।

3. **संबंधित देश:-** वर्तमान जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ तथा ताईवान हैं (जिन्हें इसमें इसके बाद सम्बद्ध देश भी कहा गया है)।
4. **समान वस्तुएं:-** याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके द्वारा उत्पादित माल, सम्बद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित माल के समान वस्तुएं हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित माल को, नियमावली के अर्थों के भीतर सम्बद्ध देशों से आयातित माल के समान वस्तुएं माना जा रहा है।
5. **सामान्य मूल्य:-** याचिकाकर्ता ने ताईवान में बिसफिनोल-ए के उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर ताईवान में सामान्य मूल्य का दावा किया है। यूरोपीय संघ (ई यू) के निर्यातकों के संबंध में याचिकाकर्ता ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों यानि नीदरलैंड तथा बैल्जियम के बीच सम्बद्ध वस्तुओं की बिक्री के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। नीदरलैंड और बैल्जियम यूरोपीय संघ के हिस्से हैं और दोनों का सीमाशुल्क क्षेत्र एक समान है। इस प्रकार, समूचे यूरोपीय संघ के लिए कीमतें समान रूप से बाध्यकारी होंगी। प्राधिकारी के पास यूरोपीय संघ तथा में बिसफिनोल-ए की प्रचलित घरेलू कीमत को दर्शाने वाले पर्याप्त साक्ष्य हैं।
6. **निर्यात-कीमत:-** याचिकाकर्ता ने डीजीसीआईएण्डएस (कलकत्ता) तथा दूसरे स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। याचिकाकर्ता ने कारखानागत कीमत का हिसाब लगाने के लिए समुद्री भाड़े, बीमे, कमीशन तथा बंदरगाह पर हैंडलिंग प्रभार के लिए समायोजन की मांग की है।
7. **डम्पिंग मार्जिन:-** इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि सम्बद्ध वस्तुओं का सम्बद्ध देशों में सामान्य मूल्य, उस मूल्य से बहुत अधिक है जिस पर इसे भारत को निर्यात किया गया। इस बात से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि निर्यातकों द्वारा सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।
8. **क्षति:-** क्षति से संबंधित विभिन्न मानदण्ड जैसे गिरती हुई घरेलू कीमतें, आयातों की मात्रा में वृद्धि तथा याचिकाकर्ता का उत्पादन की उचित लागत प्राप्त करने में असमर्थ रहना इत्यादि समग्र तथा संचयी रूप से प्रथम दृष्टया बताते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण आर्थिक क्षति हुई है।
9. **पाटनरोधी जांच का आरंभ:-** उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, सम्बद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं की कथित डम्पिंग होने उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटन-रोधी जांच आरंभ करते हैं।
10. **जांच की अवधि:-** वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 1998 से 30 सितम्बर, 1999 (18 महीने) तक की है।
11. **सूचना देना:-** सम्बद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित रूप में तथा निर्धारित ढंग से निर्दिष्ट प्राधिकारी, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, पाटनरोधी तथा सम्बद्ध शुल्क निदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेज दें। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि की सीमा के

12. **समय सीमा:** -वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।
13. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:** नियम 6(7) के अनुसार रुचि रखने वाली कोई भी पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।
14. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती हैं तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

रत्ति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE

### (Initiation Notification)

New Delhi, the 6th January, 2000

**Subject :** Initiation of anti-dumping investigation concerning import of Bisphenol-A from European Union (EU) and Taiwan.

**No. 47/1/99/DGAD.**—M/s Kesar petroproducts Limited, 7, Nagin Mahal, 82 V N Road, Churchgate, Mumbai-400 020, has filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Bisphenol-A from European Union and Taiwan and requested for anti dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

1. **Product Involved:** The product involved in the present investigation is Bisphenol-A (also referred as subject goods hereinafter) originating in or exported from the European Union and Taiwan. Bisphenol-A finds uses in Phenolic resins, Epoxy resins, Polycarbonate resins and Unsaturated Polyester resins and is classified under Customs Sub-heading 2907.23 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
2. **Domestic Industry Standing:** M/s. Kesar Petroproducts Limited, Mumbai is the only producer of Bisphenol-A in India and hence the petitioner satisfies the standing to file the petition on behalf of the domestic industry.
3. **Countries involved:** The countries involved in present investigation are European Union and Taiwan (also referred to as subject countries hereinafter).

4. **Like Articles:** The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods, originating in or exported from the subject countries. Goods produced by the petitioner are being treated as like articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules.
5. **Normal value:** The petitioner has claimed Normal Value in Taiwan based on constructed cost of production of Bisphenol-A in Taiwan. As regards exporters from European Union (EU), petitioner has furnished evidence on sale of subject goods between member countries of European Union i.e. Netherland and Belgium. Netherland and Belgium are part of the European Union and having a common custom territory. Thus, the prices in whole of European Union are bound to be the same. The Authority has sufficient prima-facie evidence, indicating the prevailing domestic price of Bisphenol-A in European Union.
6. **Export price:** The petitioner has claimed the export price based on data compiled by the DGCI&S, Calcutta as well as secondary sources. The petitioner has further claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, commission and port handling charges to arrive at the ex-factory price.
7. **Dumping Margin:** There is sufficient prima-facie evidence that the Normal Value of the subject goods in subject countries is significantly higher than the price at which it has been exported to India indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by exporters from subject countries.
8. **Injury:** Various parameters relating to injury such as suppressed domestic prices, increase in quantum of imports and the petitioner being unable to recover its fair cost of production etc. prima-facie indicate collectively and cumulatively that domestic industry has suffered material injury on account of dumping.
9. **Initiation of Anti-Dumping Investigation:** The Designated Authority, in view of the foregoing paragraph, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries
10. **Period of Investigation:** The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April, 1998 to 30th September, 1999 (18 months).
11. **Submission of Information:** The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below

12. **Time Limit:** Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.
13. **Inspection of Public File:** In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
13. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

